भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की लॉन्च

देवभूमि मिरर/चंडीगढ़। भारत की पहली एआई-पावर्ड, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के चेयरमैन उदय उमेश ललित द्वारा जयपुर में किया गया। राजस्थान राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के टेक्नोलॉजी पार्टनर ज्युपीटाईस टेक्नोलॉजीज द्वारा इस डिजिटल लोक अदालत का डिज़ाइन और अवधारणा विकसित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना द्वारा कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में किया गया। डिजिटल लोक अदालत के माध्यम से पुराने लंबित मामलों का निपटान किया जा सकेगा या ऐसे मामलों को भी आसानी से निपटाया जा सकेगा जो आरंभिक चरण में हैं। इससे विवाद निपटान की प्रक्रिया आधुनिक बनेगी, जहां आवेदन के ड्राफ्ट और फाइलिंग से लेकर एक क्लिक पर ई-नोटिस जनरेशन, स्मार्ट टेम्पलेट, ड्राफ्ट सेटलमेंट समझौता और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डिजिटल सुनवाई तक सभी पहलुओं को बढ़ावा मिलेगा। ज्युपीटाईस देश के विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थानों और एडीआर सेंटरों के साथ काम कर रही है ताकि विवादों के निपटान के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा सके। ज्युपीटाईस ने न्याय प्रणाली की मौजूदा समस्याओं को हल करने के लिए गहन अनुसंधान के बाद डिजिटल लोक अदालत की अवधारणा डिजाइन और विकसित की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेब, मोबाइल और सीएससी के ज़रिए देश के दूरदराज के इलाकों तक भी न्याय पहुंचे तथा अन्य सेवाओं की तरह न्याय को किफायती बनाया जा सके।